भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1760
03.08.2026 को उत्तर देने के लिए

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जनता की शैक्षिक अर्हता

1760. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2025 के अनुसार देश में कितने व्यक्तियों ने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों में से न्यूनतम तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है;

(ग) उक्त सर्वेक्षण में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में रोजगार तथा शिक्षा का प्रतिशत कितना है; और

(घ) इस अंतराल को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की जा रही है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 67.8 प्रतिशत व्यक्तियों ने कम-से-कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है।

(ख): पीएलएफएस, 2025 के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के 4.3 प्रतिशत व्यक्तियों ने कम-से-कम एक तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

(ग): पीएलएफएस, 2025 के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार 15–29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 41.4 प्रतिशत है। 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में शिक्षा के अनुमान पीएलएफएस 2025 में उपलब्ध नहीं है।

(घ): रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। तदनुसार, सरकार द्वारा देशभर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कौशल भारत मिशन (एसआईएम) शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए सक्षम बनाना, उन्हें उद्योग कौशल से युक्त करना है। कार्यबल के ट्रांजिशन, पुनर्नियोजन तथा

उभरती हुई रोजगार भूमिकाओं के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से पुनः कौशल तथा कौशल उन्नयन संबंधी पहलें की जा रही हैं। यह कार्यक्रम एआई आधारित अर्थव्यवस्था में रोजगार क्षमता सुनिश्चित करने के लिए संरचित कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता तथा उन्नत प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि तथा सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सहयोग देने के उद्देश्य से, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का कार्यान्वयन कर रही है। रू. 99,446 करोड़ के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का संचालन कर रहा है, जो एक डिजिटल मंच के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार संबंधी जानकारी, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रोजगार मेलों, रोजगार खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि सहित करियर संबंधी सेवाएँ प्रदान कराने हेतु एक वन-स्टॉप समाधान है (www.ncs.gov.in)।

*****